

न्यायालय राजरव मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम०के० सिंह
सादरय

निगरानी प्र० क० 1268-तीन/2013 विरुद्ध आदेश दिनांक 05-03-13
पारित आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 198/2011-12
अपील.

फतेह सिंह पुत्र रणधीरसिंह सेंगर
निवासी थोराट की गोठ, लोहिया बाजार,
लशकर, ग्वालियर कृषक ग्राम गोधन,
तहसील चंदेरी, जिला अशोकनगर, म०प्र०
विरुद्ध

— आवेदक

राजकुमार सिंह पुत्र कुन्दनसिंह (मृत)
वारिसान—

- 1- श्रीमती उषादेवी पत्नी स्व. राजकुमार
 - 2- शिवप्रताप सिंह पुत्र स्व. राजकुमार
 - 3- कृष्णा पत्नी अजयप्रताप सिंह तोमर
 - 4- मीनाक्षी पुत्री स्व. राजकुमार सर. संजीवसिंह
- समस्त नि० न्यू बस स्टैन्ड के पास पंचमढी
तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर, म०प्र०


— अनावेदकगण

श्री सी०एम० गुप्ता, अभिभाषक — आवेदक
श्री जितेन्द्र त्यागी, अभिभाषक— अनावेदकगण

आदेश

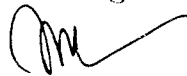
(आज दिनांक २५ जुलाई, 2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे
आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत आयुक्त, ग्वालियर
संभाग, ग्वालियर के अपील प्रकरण क्रमांक 198/2011-12 में पारित आदेश
दिनांक 05-03-13 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।



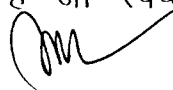
2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम गोधन स्थित कुल रकबा 7.665 हे० भूमि आवेदक फतेहरिंह पुत्र रणधीरिंह एवं सुरेन्द्रिंह पुत्र कुन्दनरिंह के नाम राजस्व अभिलेख में भूमिरवामी स्वत्व में दर्ज थी। इस प्रश्नाधीन भूमि के 1/2 हिस्से पर बाप के जमाने से काबिज होकर खेती करने के आधार पर अनावेदक राजकुमार ने कब्जा अंकित करने हेतु आवेदनपत्र संहिता की धारा 115/116 के अन्तर्गत तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया। तहसीलदार ने दिनांक 4-11-96 को प्रकरण दर्ज कर इशतहार जारी करने तथा पटवारी रिपोर्ट मँगाने के आदेश दिये। तत्पश्चात् दिनांक 17-1-97 को आवेदक साक्षी रामदयाल तथा भगवानरिंह के कथन अंकित करने के बाद प्रकरण आदेश हेतु नियत किया। तहसीलदार ने आदेश दिनांक 14-2-97 द्वारा फतेहरिंह के स्वत्व की प्रश्नाधीन भूमि के 1/2 हिस्से पर राजकुमार पुत्र कुन्दनरिंह का संवत् 2053 से निरन्तर कब्जा मानकर खसारे में अंकित करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरुद्ध फतेहरिंह द्वारा प्रस्तुत अपील अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 09 08 12 द्वारा समयावधि बाह्य मानकर खारिज की। द्वितीय अपील आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 05-03-13 द्वारा सिविल न्यायालय में स्वत्व का प्रकरण प्रचलित होने से खारिज की गयी है। अतः आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की है।

3/ मैंने अधीनस्थ न्यायालयों के उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया। आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदक के भूमिरवामी स्वत्व में राजस्व अभिलेख में अंकित है। तहसील न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जा अंकित करने के पूर्व आवेदक को सूचनापत्र तामील नहीं किया और ना ही उन्हें सुनवायी का अवसर प्रदान किया। आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी होने पर अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी। उनका यह भी तर्क है कि



संहिता की धारा 115/116 के अन्तर्गत नवीन प्रविष्टि नहीं की जा सकती। धारा 115 के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा स्वमेव गलत प्रविष्टि का सुधार किया जा सकता है तथा धारा 116 के अन्तर्गत प्रविष्टि के दिनांक से एक वर्ष के भीतर उसके शुद्धिकरण के लिये तहसीलदार को आवेदन दिया जा सकता है। आवेदक का आवेदनपत्र संहिता की धारा 115/116 की परिधि में नहीं आता, इस कारण तहसीलदार का आदेश क्षेत्राधिकार विहीन होने से शून्यवत है और समयावधि के आधार पर अपीलीय न्यायालय ने यथावत रखने में भूल की है। उनका अन्त में यह तर्क है कि आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपील सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने के पूर्व ही प्रस्तुत की गयी। अनावेदक की जानकारी में आने पर अनावेदक द्वारा सिविल न्यायालय में स्वत्व घोषणा का वाद दायर किया गया है। सिविल न्यायालय ने दिनांक 24-01-13 को मात्र विक्रय पर रोक लगायी है, कार्यवाही स्थगित करने का आदेश नहीं दिया गया। आयुक्त द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों एवं अभिलेख आदि का अवलोकन किये बिना आदेश पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। आवेदक अभिभाषक द्वारा 2006 रा.नि. 104, 2007 आर.एन. 199 तथा 1994 आर.एन. 411 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4/ अनावेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि प्रश्नाधीन भूमि के 1/2 भाग पर अनावेदकगण के पिता का कब्जा बेरोक-टोक निरन्तर बाबा के समय से है। पटवारी द्वारा खसरे में कब्जा अंकित नहीं किये जाने से अनावेदक राजकुमार द्वारा धारा 115/116 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार द्वारा विधिवत इशतहार प्रकाशित करने के पश्चात साक्ष्य लेने के बाद कब्जा अंकित करने के आदेश दिये हैं जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। उनका तर्क है कि आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी होने पर भी अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील 13 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है जो स्पष्टतः समयावधि बाह्य है, इस कारण

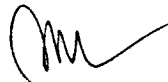


अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील समयावधि बाह्य होने से खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है। उनका अन्त में तर्क है कि रवत्व संबंधी वाद सिविल न्यायालय में प्रचलित है, इस कारण राजरव एवं सिविल न्यायालय में समान्तर कार्यवाही प्रचलित रखने का कोई औचित्य नहीं होने से विद्वान आयुक्त द्वारा अपील समाप्त करने में कोई गलती नहीं की है। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया।

5/ इस न्यायालय में तहसील न्यायालय के आदेश पत्रिकाओं एवं दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ प्रस्तुत की गयी हैं। तहसील न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं से स्पष्ट है कि तहसीलदार ने दिनांक 4-11-96 को राजकुमार द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जा दर्ज करने हेतु प्रस्तुत आवेदनपत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज कर इशतहार जारी करने तथा पटवारी ग्राम से रिपोर्ट लेने के आदेश दिये और प्रकरण दिनांक 18-12-96 को नियत किया। आदेश पत्रिका दिनांक 18-12-96 में यह अंकित है कि इशतहार का प्रकाशन किया। कोई आपत्ति नहीं आई। पटवारी ग्राम उपस्थित रिपोर्ट पेश किया। आवेदक साक्ष्य पेश करें और प्रकरण 17-1-97 को नियत किया। आदेश पत्रिका दिनांक 17-1-97 में यह अंकित है कि --

“प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक उपस्थित। साक्षी रामदयाल तथा भगवानसिंह उपस्थित। सभी के कथन अंकित किये गये। प्रकरण आदेशार्थ सी एफ 14-2-97.”

तहसीलदार ने आदेश दिनांक 14-02-97 को फतेहसिंह के रवत्व की 1/2 भूमि पर अनावेदक राजकुमार का कब्जा संवत् 2053 से निरन्तर मानकर खसरे में कब्जा अंकित करने के आदेश दिये हैं। इससे स्पष्ट है कि आवेदक फतेहसिंह प्रश्नाधीन भूमि का अभिलिखित भूमिरवामी होने के बाद भी तहसीलदार द्वारा आदेश पारित करने के पूर्व ना तो उसे प्रकरण में पक्षकार बनाया और ना ही सूचनापत्र जारी कर सुनवायी का अवसर प्रदान किया। यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि संहिता की धारा 115 के अन्तर्गत तहसीलदार



द्वारा स्वमेव गलत प्रविष्टि का सुधार किया जा सकता है तथा धारा 116 के अन्तर्गत प्रविष्टि के दिनांक से एक वर्ष के भीतर उसके शुद्धिकरण के लिये तहसीलदार को आवेदन दिया जा सकता है अर्थात् संहिता की धारा 115 एवं 116 के अन्तर्गत गलत प्रविष्टि का सुधार किया जा सकता है और कोई नवीन प्रविष्टि करने के आदेश धारा 115/116 के अन्तर्गत नहीं दिये जा सकते। चंदनसिंह विरूद्ध कृपालसिंह (2006 रा.नि. 104) में राजरव मण्डल द्वारा यह व्यवस्था दी गयी है कि -

“धारा 121, 115 तथा 116- नि. 7 तथा 8 (धारा 121 के अधीन)- नियमों में खरसरा तैयार करने के लिये निर्देश और प्रक्रिया का उपबन्ध है- नियमों के अधीन कोई मामला विनिश्चित नहीं किया जा सकता - किसी भी धारा 115, 116 तथा 121 के अधीन कब्जा अभिलिखित नहीं किया जा सकता- कब्जा अभिलिखित करने के लिये धारा 121 के अधीन तहसील न्यायालय के रामक्ष आवेदन फाइल नहीं किया जा सकता।

धारा 116- न तो नया अधिकार सिद्ध किया जा सकता है और न नयी प्रविष्टि की जा सकती है।”

रामस्वरूप वि. कलावती तथा अन्य (2007 रा.नि. 199) में भी राजरव मण्डल द्वारा यह व्यवस्था दी है कि -

“धारा 115,116 तथा 32- अधिकार अभिलेख में किसी का कब्जा अभिलिखित करने के लिए अधिकारिता नहीं- धारा 116 के अधीन एक वर्ष के भीतर अधिकार-अभिलेख में गलतियाँ ठीक की जा सकती हैं - धारा 115 तहसीलदार को कार्यवाही करने के लिये सशक्त करती है- धारा 32 का उपबन्ध वहाँ लागू होता है जहाँ संहिता में कोई अन्य उपबन्ध नहीं है।

धारा 121, नि. 6 से 11- कब्जा अभिलिखित करने की शक्ति- उपबन्धों के अधीन तहसीलदारों को उपलब्ध नहीं।”

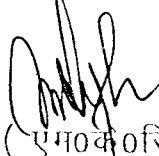
ग्वालियर एग्रीकल्चरल कं. लि. डबरा वि. छोटेलाल तथा अन्य (1994 रा.नि. 411) में भी राजरव मण्डल द्वारा यह निर्धारित किया है कि धारा 115 तथा



116 के अधीन पूर्व में विद्यमान प्रविष्टि शुद्ध की जा सकती है, नई प्रविष्टि नहीं की जा सकती। तहसीलदार द्वारा कब्जा प्रविष्टि का आदेश अधिकारिता रहित है।

6/ उक्त विवेचना से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा आदेश पारित करने के पूर्व ना तो आवेदक को अभिलिखित भूमिस्वामी होते हुए प्रकरण में पक्षकार बनाया और ना ही उसे सुनवायी का कोई अवसर प्रदान किया। तहसील न्यायालय को संहिता की धारा 115/116 के अधीन खसारे में कब्जे की नवीन प्रविष्टि करने की अधिकारिता नहीं है, इस कारण तहसीलदार का खसारे में कब्जे की नवीन प्रविष्टि करने का आदेश देना अधिकारिता विहीन है। प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त के विपरीत तथा अधिकारिता रहित आदेश को अनुविभागीय अधिकारी ने समयावधि के आधार पर तथा आयुक्त ने सिविल न्यायालय में स्वत्व का वाद विचाराधीन होने से यथावत रखने की त्रुटि की है।

7/ उपरोक्त स्थिति में निगरानी रवीकार की जाती है। आयुक्त का आदेश दिनांक 05-03-13, अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 09-08-12 तथा तहसीलदार का आदेश दिनांक 14-02-97 निरस्त किये जाते हैं।


(एम०के०सिंह)
सदस्य,

राजरव मण्डल, म०प्र०
ग्वालियर,